

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-3

देहरादून, दिनांक: 20 मार्च, 2008

**विषय:-** सैफ खेलों के आयोजन हेतु भानियावाला-धानों-रायपुर-सहस्रधारा तक 4 लेन फास्ट ट्रैक के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1/कैम्प देहरादून के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वर्ष 2009 में प्रस्तावित सैफ खेलों के आयोजन हेतु प्रश्नगत मार्ग के 4 लेन फास्ट ट्रैक निर्माण हेतु रुपये 11328.80 पर टी.ए.सी. वित्त के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रुपये 9513.00 लाख (रुपये पियानवे करोड़, तेरह लाख मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2007-08 में रुपये 4756.00 लाख (रुपये सैतालीस करोड़, छप्पन लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन पर रखते हुये व्यय किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. स्वीकृत धनराशि आहरित करके व्यय हेतु जमा मद (Deposit Work) में रखी जाय।
2. व्यय उसी कार्य पर किया जाय, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
3. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, नियम तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-2 विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का मदवार विवरण शासन/भारत सरकार को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा।
5. धनराशि का व्यय करने में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जावेगा और उक्त धनराशि के विपरीत भारत सरकार से अविलम्ब आवश्यक धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।
6. निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणन पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय और आगणन में ली गई रोड का सत्यापन अधीक्षण अभियन्ता से कराकर इसकी सूचना शासन को दी जायेगी।
7. उक्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

31/3/08

8. स्वीकृत की जा रही धनसशि को दिनांक 31.03.2008 तक उपयोग कर लिया जायेगा और इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भारत सरकार व राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जायेगा।
9. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-07 के लेखा शीर्षक-4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत व्यय परिव्यय-80 सामान्य- आयोजनागत- 800 अन्य भवन-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रपुरोनिधानित योजना-0101 -12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत राज्य अवस्थापना विकास-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
10. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अ.शा. संख्या 319/XXVII(2)/08 दिनांक 20 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्याकी)  
अपर सचिव।

पृ.सं. 105(1)/111(3)2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तराखण्ड, इलाहाबाद/देहरादून।
- 2- अनु सचिव, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पीडी।
- 5- मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, पीडी/अल्मोड़ा।
- 6- अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8- सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 9- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- लोक निर्माण अनुभाग-2/गार्ड बुक।
- 11- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12- गार्ड बुक।

आज्ञा से

प्रदीप सिंह रावत

(प्रदीप सिंह रावत)  
उप सचिव।